उत्तराखण्ड शासन कर्जा अनुमाग—2 संख्याः 1295/I(2)/2017-05-34/2016 देहरादून दिनांक 17, अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड, 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुमाग—7 की अधिसूचना संख्या—290/xxvi(7) 50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के कम में ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों की स्वीकृति शासनादेश संख्या—1199/I(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के माध्यम से प्रदान की गयी थी।

2— उक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिक संगठनों / एसोसियेशनों द्वारा उक्त शासनादेश के साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स स्लैब में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वेतन मैट्रिक्स स्लैब से भिन्न होने तथा पूर्ववर्ती ए०सी०पी० व्यवस्था परिवर्तित होने से कार्मिकों को सम्भावित आर्थिक हानि होने के कारण संशोधन किये जाने का शासन से अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में तथा पुनः सचिव, ऊर्जा की अध्यक्षता में तीनों निगमों के प्रबन्धनों एवं कर्मचारी संगठनों / एसोसियेशनों के साथ दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को बैठक आहूत की गयी।

3— सचिव, ऊर्जा द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 की बैठक में निम्न समिति गठित करने का आदेश दिया गया:—

1.	श्री रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शा	सन—	अध्यक्ष
	श्री एस0एन0 वर्मा, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएनएल	_	सदस्य
	श्री बी0सी0के0 मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल	-संयो	जक / सदस्य
4.	श्री एल०एम० वर्मा, निदेशक वित्त, यूजेवीएनएल / यूपीसीएल	-	सदस्य
	श्री अमिताम मैत्रा, निदेशक, वित्त, पिटकुल	_	सदस्य
	श्री पी0सी0 ध्यानी, निदेशक, मानव संसाधन, यूपीसीएल		सदस्य
7.	श्री सुधीर कुमार, उत्तरांचल पावर इंजीनियर एसोसियेशन	-	सदस्य
, 8.	्श्री संदीप शर्मा, उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसियेशन	_	सदस्य
9.	श्री दीपक बेनीवाल, उत्तराखण्ड ऊर्जा कामगार संगठन		सदस्य
10	. श्री दीपक शैली, ऊर्जा आफिर्सस सुपरवाईर्जस एण्ड स्टाफ एसोसिये	शन—	सदस्य

उक्त समिति को यह निर्देशित किया गया कि:--

1. समिति उक्त शासनादेश के साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स स्लैब एवं निदेशक मण्डल द्वारा पारित मैट्रिक्स स्लैब का परिशीलन एवं अध्ययन करने के उपरान्त कार्मिकों को होने वाली सम्भावित वित्तीय हानि का परीक्षण एवं आंकलन कर अपनी आख्या / रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत् करेगी।

कमशः पेज-2

2. ऊर्जा के तीनों निगमों में विद्यमान ए०सी०पी० व्यवस्था (०९ वर्ष, ०५ वर्ष एवं ०५ वर्ष) के स्थान पर एम०ए०सी०पी व्यवस्था (१० वर्ष, १० वर्ष एवं १० वर्ष) लागू होने पर कार्मिकों को होने वाली सम्भावित वित्तीय हानि का परीक्षण एवं आंकलन कर अपनी आख्या/रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

यह समिति उक्त 02 बिन्दुओं पर यथाशीघ्र अपनी आख्या/रिपार्ट सचिव, ऊर्जा को प्रस्तुत करेगी जिसका उच्च स्तर पर परीक्षण कर 01 माह के अन्दर निर्णय लिया जायेगा।

> (रणवीर सिंह चौहान) अपर सचिव

संख्याः 1295 /I(2)/2017-05-34/2016 तद्दिनांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

- 1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 2. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3. निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4. निजी सचिव, सचिव, ऊर्जा, उत्तरखण्ड शासन।
- 5. समस्त समिति के सदस्यगण।
- 6. गार्ड फाइल।

(रणवीर सिंह चौहान) अपर सचिव

J.